डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जुलाई, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 जुलाई, 2022

| वर्ष 66 | अंक 04 | भोपाल | 16 जुलाई, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता से बदलेगी भारत की तस्वीर, अमित शाह ने कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, पीटीआई, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बेहतर जीवन जीने की इच्छा रखने वाले 70 करोड़ गरीबों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 100वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Co-operative Day 2022) के उपलक्ष्य में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने सहकारी समितियों से इन 70 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा।

सहकारी समितियों की बड़ी जिम्मेदारी

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में गरीबों के उत्थान के साथ - साथ उनके लिए बिजली. रसोई गैस , आवास और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये 70 करोड़ लोग अब बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे है और इस लक्ष्य को केवल सहकारी क्षेत्र द्वारा ही पूरा किया जा सकता है | "Co-operatives Build An Atmanirbhar Bharat and Better World" विषय पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पूंजीवाद और साम्यवाद शासन के चरम रूप है और विकास का सहकारी मॉडल देश के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को पेशेवर और बहुआयामी बनाकर विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है।

अमित शाह ने कहा कि कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय (co-operative university) स्थापित किया जाएगा। इसमें एकाउंटिंग, मार्केटिंग ओर मेनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। इसके अलावा सरकार ने सभी 63000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACs) का कंप्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है। इस कदम से लेखांकन और बहीखाता पद्धति में पारदर्शिता आएगी। इस कार्य पर 2.516 करोड़ रुपये खर्च होगे । चूंकि ऐसी समितियां राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जा रहे है। मोदी सरकार ने PACS को multipurpose करने के Model Bye-Laws बनाकर सभी प्रदेशों को सुझाव देने के लिए भेजें हैं। जल्द ही PACS multipurpose बनेंगे। Multipurpose होने में PACS का दायरा तो बढ़ेगा ही साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत में सहकारिता की स्थिति

भारत में 8.5 लाख सहकारी समितिया है और लगभग 12 करोड़ लोग इस क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं। दूध, उर्वरक, चीनी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण और खाद्यान्न की खरीद जैसे कई व्यवसायों में सहकारी समितियों का योगदान अहम है। अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियों के विस्तार पर जोर दिया।

मोदी सरकार द्वारा 63,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट ने लगभग 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पैक्स सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यू टरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2,516 करोड़ रुपये की लागत से 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को लाभ होगा। इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और यह बहुउद्देशीय पैक्स को लेखांकन की सुविधा भी देगा ।

श्री अमित शाह ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयरस्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। साथ ही इससे पैक्स कोप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस), फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और खाद, बीज आदि इनपुट प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी।

2025 तक यूरिया आयात की आवश्यकता नहीं होगी- केंद्रीय उर्वरक मंत्री मांडविया

नई दिल्ली। (भाषा) केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत को वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की सालाना डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

वर्तमान में देश में यूरिया उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि पूरे देश की डिमांड को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन यूरिया का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार आयात में कमी होने से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, ''हमारा अनुमान है कि हम 2025 के अंत तक यूरिया मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और आयात पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। पारंपरिक यूरिया और नैनो (nano) यूरिया का भारत में उत्पादन मांग से अधिक होगा।''

श्री मांडविया ने कहा कि पारंपरिक यूरिया के लिए लगभग 60 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ बोतल (प्रत्येक 500 मिलीलीटर) प्रतिवर्ष होने का अनुमान है, जो 200 लाख टन पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा।

नैनो यूरिया के उपयोग से छोटे किसानों को लाभ

श्री मांडविया ने कहा कि कृषकों ने नैनो यूरिया को अच्छी तरह अपनाया है जो बहुत उत्साहजनक है। नैनो यूरिया की एक बोतल यूरिया की एक बोरी के बराबर होती है। मौजूदा समय में नैनो यूरिया का उत्पादन पांच करोड़ बोतल प्रतिवर्ष का हो रहा है। इफको नैनो यूरिया को 240 रुपये प्रति बोतल (500 मिलीलीटर) की दर से बेच रही है।

इफको द्वारा नैनो यूरिया का उत्पादन एक अगस्त, 2021 को गुजरात के कलोल में शुरू हुआ।इफको के साथ-साथ दो अन्य उर्वरक कंपनियों आरसीएफ और नेशनल फ़र्टिलाइज़र द्वारा सात और नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों की आय में औसतन 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि का अनुमान है।नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन लागत कम होगी और छोटे किसानों को लाभ होगा।

उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ा

कुल उर्वरक सब्सिडी गत वित्त वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्तवर्ष में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है।चालू वित्तवर्ष में केवल यूरिया पर ही लगभग 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी हो जाएगी।

सहकारी समितियों के आडिट का चलेगा युद्ध स्तर पर अभियान

नई दिल्ली। Audit of Cooperative: पूर्व में सहकारिता शिथिलता और भ्रष्टाचार के कारण बदनाम रही है। लेकिन इसे सक्रिय और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य जिस तरह इकट्ठे आए हैं उससे साफ है कि इसकी छवि पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नाबार्ड और अन्य पक्षकारों को जहां उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं उसके क्रियान्वयन और परियोजना (Audit of Cooperative) की निगरानी के लिए विशेष समितियां गठित कर दी गई हैं।

आपरेशनल गाइडलाइंस पारित

सप्ताह भर हुए फैसले पर अमल की तैयारी को लेकर हुई नेशनल लेवल मानिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में आपरेशनल गाइड लाइंस को पारित कर दिया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने वार्षिक बजट में पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रविधान करना होगा।

फैसले पर अमल तेजी से शुरू

सहकारी क्षेत्र की प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) को डिजिटल बनाने की दिशा में लिए गए फैसले पर अमल तेजी से शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के लगभग एक सप्ताह के भीतर ही राज्य व अन्य पक्षकारों के साथ सहमति बना ली

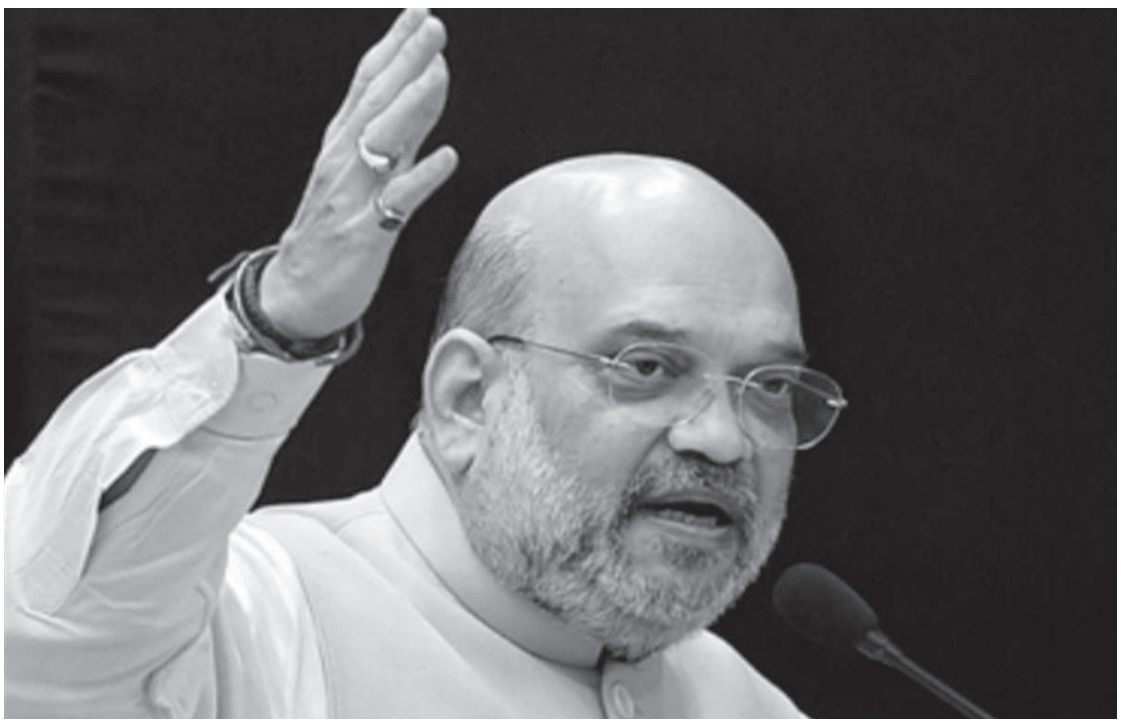

गई। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इसके पहले चरण में सभी प्रदेशों में राज्य और जिला स्तरीय निगरानी व क्रियान्वयन समिति (Audit of Cooperative) का गठन किया जाएगा।

आडिट के लिए चलाया जाएगा अभियान

इसके साथ ही बैठक में यह तय किया गया कि जिन पैक्स को कंप्यूटराइजेशन प्रस्तावित किया जाए, उसका पहले आडिट जरूर करा लिया जाए। इसके लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में युद्ध स्तर पर आडिट के लिए अभियान चलाया जाएगा। पैक्स कंप्यूटराइजेशन का यह पहला चरण होगा।

होंगे ये फायदे

इन्हें सहकारी समितियों (Audit of Cooperative) के नाम भी जाना जाता है। सहकारी समितियों (पैक्स) की सक्रियता से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजी रोजगार बढ़ेगा, वहीं किसानों को स्थानीय स्तर पर बीज, फर्टिलाइजर व कीटनाशक उपलब्ध होने लगेगा। उनकी उपज की बिक्री में सहयोग और रियायती कर्ज मिलने में सहूलियत मिलेगी।

पैक्स गठित करने का लक्ष्य निर्धारित

देश में फिलहाल 63 हजार पैक्स सक्रिय है, जबकि 32 हजार पैक्स विभिन्न अनियमितताओं और गड़बड़ियों के चलते निष्क्रिय पड़ी हुई है। बायलाज में मामूली संशोधन के साथ उन्हें सक्रिया करने के साथ देशभर में तीन लाख पैक्स गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे देश की सभी ग्राम पंचायतें कवर हो जाएंगी।

2500 करोड़ रुपए मंजूर

इनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इनके कंप्यूटराइजेशन के बाबत केंद्रीय कैबिनेट ने 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पारित आपरेशनल गाइडलाइंस में पैक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध प्रत्येक पक्षकार का दायित्व निर्धारित कर दिया गया है। पैक्स कंप्युटराइजेशन वाली परियोजना में राज्यों को 30 फीसद खर्च करना होगा।

साफ्टवेयर के प्रावधानों पर सौंपी गई जिम्मेदारी

इसके लिए उन्हें बजटीय प्राविधान करना होगा। इसके लिए राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। कंप्यूटराइजेशन के लिए चिन्हित अथवा चयनित पैक्स के प्रस्ताव तैयार करने और उसके लिए साफ्टवेयर के प्रविधानों पर केंद्र, राज्य, जिला व नाबार्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

परियोजना की होगी निगरानी

परियोजना को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिला स्तर तक समितियां असल फैसला लेंगी। राष्ट्रीय स्तर की निगरानी व क्रियान्वयन समिति की बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, नाबार्ड के चेयरमैन व उसके अन्य आला अफसर और नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जबकि बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार ने की।

प्रधानमंत्री के विजन से बन रहे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बदलेगी राज्यों की तकदीर एवं तस्वीर : मुख्यमंत्री श्री चौहान

केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक

मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर से हुए बैठक में शामिल

भोपाल : केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में केन्द्रीय रेल एवं उद्योग मंत्री सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से बैठक में वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का ही कमाल है कि देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं, जो राज्यों की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। उनके विजन से दिशा मिलती है और इससे तेज गति से काम करने का प्रयास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि मध्यप्रदेश ने तेज गति से काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की और कहा कि विक्रम उद्योगपुरी को 202 एकड़ जमीन अलाट कर दी गई है। इसमें 20 उद्योगपति जमीन भी ले चुके हैं और कई ने काम भी प्रारंभ कर दिए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर में एक कंपनी प्रोडक्शन प्रारंभ कर देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 कंपनी के आवेदन आ चुके हैं, जिन्हें बहुत जल्द लैंड अलॉट कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उद्योगपतियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्यप्रदेश वैसे भी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टेट है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, जिससे निवेश आने की गति न रूके। उन्होंने डेलिगेशन ऑफ पावर को आश्वस्त किया कि वे तत्काल इस कार्य को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली-नागपुर कॉरिडोर के संबंध में कहा कि मध्यप्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ से यह निकलेगा, वहाँ भारतमाला परियोजना में 330 किलोमीटर में अटल एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए योजना भी तैयार की जा चुकी है। इसके लिए 11 हजार एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे पूरी तत्परता के साथ समय-सीमा में विभिन्न परियोजना पर काम कर पूरा करेंगे। उन्होंने दिल्ली -नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रस्ताव को प्राथमिकता से बनाने को कहा। इससे आगरा, मुरैना, ग्वालियर, गुना, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल और नागपुर में बेहतर तरीके से उद्योग लाये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कई जगह अलग-अलग क्लस्टर चिन्हित कर जमीन देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा वाराणसी-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्वी मध्यप्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। एल्युमीनियम, कोयला और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में है। यदि पूर्वी मध्यप्रदेश को पश्चिम से जोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में बेहतर रोड कनेक्टिविटी और मार्केट विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में निश्चित समय-सीमा में कार्य होगा। उन्होंने कदम से कदम तथा कंधे से कंधा मिला कर कार्य करने के साथ प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने को कहा।

भोपाल, जबलपुर भी कृषि उड़ान हवाई अड्डों में शामिल होंगे

कृषि उड़ान 2.0 पर हितधारक मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन

नई दिल्ली । नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से कृषि उड़ान 2.0 के मूल्यांकन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस सम्मेलन में हवाई कार्गो क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ लाया गया ताकि वे कृषि उड़ान के लाभों को उजागर करते हुए बता सकें कि किस प्रकार घरेलू हवाई कार्गो कंपनियां के साथ मिलकर काम कर सकती हैं और पूरी मूल्य श्रृंखला में निर्बाध लेनदेन सृजित कर सकती हैं।

कार्यशाला की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल ने की और कार्यक्रम का संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी द्वारा किया गया। कार्यशाला में मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री पीयूष श्रीवास्तव,

रक्षा मंत्रालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संयुक्त सचिव श्री सौरभ एंडले, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आशुतोष डे, एएआईसीएलएएस के सीईओ श्री अजय कुमार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एएआईसीएलएएस, फिक्की, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, देश भर से 26 हवाई अड्डा निदेशक (एपीडी) एवं भारतीय हवाई कार्गो क्षेत्र के अन्य विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी ने कृषि उड़ान 2.0 मूल्यांकन पर एक प्रस्तुति दी। इसमें कृषि उद्योग की उपलब्धियों, दायरे, प्रभाव और कृषि उड़ान के भविष्य पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न हवाई अड्डों के संबंध में इस योजना के प्रदर्शन पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह भी बताया गया कि 5 नए हवाई अड्डों- बेलगावी, झारसुगुडा, जबलपुर, दरभंगा और भोपाल को मौजूदा 53 कृषि उड़ान हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया जाना है। इसके साथ ही कृषि उड़ान में 58 हवाई अड्डे सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

श्रीमती रश्मि ने मण्डी बोर्ड के आयुक्त-सह-प्रबंध संचालक का कार्यभार किया ग्रहण

भोपाल : श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने सोमवार को मण्डी बोर्ड के आयुक्त-सह-प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के अधिकारियों से बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की।

नवागत एमडी श्रीमती रश्मि ने अधिकारियों को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए कहा कि मण्डी बोर्ड को आईटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। श्रीमती रश्मि का मण्डी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

फसल बीमा के लिये बैंकों को निर्देश जारी

फसल में परिवर्तन की सूचना 29 जुलाई तक दें बैंकों को

भोपाल : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

अपर संचालक फसल बीमा ने बताया कि किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी।

एनसीआईपी पर भू-अभिलेख एकीकरण का कार्य जारी

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा।

बीमा पॉलिसी के लिये एनसीआईपी पर जानकारी दर्ज होना जरूरी

किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिये नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

रूस्तमजी अवार्ड मिलेगा पुलिस विभाग के उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को : गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को 3 श्रेणी में 'रूस्तमजी अवार्ड' प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी अभियानों, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, साम्प्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्थाओं की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अवार्ड मिलेगा।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि सरकार ने उत्कृष्ट अधिकारी-कर्मचारियों को 'रूस्तमजी अवार्ड' पुन: प्रदान करने का निर्णय लिया है। पुरस्कार की परम विशिष्ट श्रेणी में 5 पुरस्कार 5-5 लाख रूपये, अति विशिष्ट श्रेणी में 6 पुरस्कार 2-2 लाख रूपये, विशिष्ट श्रेणी के 50-50 हजार रूपये के 50 पुरस्कार के साथ प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि रूस्तमजी अवार्ड पुन: प्रदान किये जाने से प्रदेश के कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों में नई स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार होगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एग्रीस्टेक संचालन समिति गठित

भोपाल : कृषकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ कृषक डिजिटली प्राप्त कर सकें एवं कृषि कार्यों से होने वाले लाभों में भी वृद्धि की संभावना को देखते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा Agristack Digital Agriculture विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एग्रीस्टेक विकसित किये जाने के लिए आई.टी. सिस्टम एवं डाटाबेस 31 मार्च 2023 तक तैयार किया जाना है।

इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की है। समिति के सदस्य सचिव आयुक्त भू-अभिलेख होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, वाणिज्यिक कर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारिता और अधिक प्रासंगिक - श्री जोशी

रतलाम, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में सहकारिता और अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज विश्व आर्थिक मंदी के द्वार पर खड़ा है। रोजगार की भारी कमी हो गई है। न तो पूंजीवाद सफल हो रहा है ओर न ही समाजवाद, ऐसी स्थिति में सहकारी दर्शन भारत को नई ऊँचाईयों तक ले जा सकता है। सहकारिता एक सब के लिए और सब एक के लिए की भावना पर काम करता है। यह पूंजीवाद और समाजवाद का मध्य मार्ग है।

उक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार व सहकारी चिंतक शरद जोशी ने जिला सहकारी संघ मर्यादित रतलाम के पुराना कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय पर 100 वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठि में व्यक्त किए।

श्री जोशी ने कहा कि माननीय अमित शाहजी के देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने से सहकारी आन्दोलन में नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। अमित शाह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं में कार्य किया है तथा वे इसकी कार्यप्रणाली को बखूबी जानते हैं।

इस अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के पूर्व प्राचार्य निरंजनकुमार कसारा ने कहा कि 100 वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की इस वर्ष की मुख्य थीम है- 'सहकारिता द्वारा बेहतर विश्व का निर्माण' सहकारिता के माध्यम से हम आर्थिक भागीदारी, पर्यावरण एवं जलवायु संतुलन, खाद्य सुरक्षा, खेती, दूध एवं ऐसे अनेक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करके एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं।

जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार हम सौवां अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना एवं इसके

माध्यम से सहकारी आन्दोलन को आगे ले जाना है। इस अवसर पर सहकारी नेता गुलाबराव जगदाले, पंकज शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संघ के जनसम्पर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने किया एवं आभार विश्वास शर्मा ने किया।

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। अब साधारण मृत्यु होने पर 8 लाख के स्थान पर 10 लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

इसी तरह निर्वाचन के समय हिंसक गतिविधियों के दौरान होने वाली मृत्यु पर 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। अशक्तता के प्रकरणों में सामान्य परिस्थिति में 4 लाख रूपए और हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्तता पर 7 लाख 50 हजार रूपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नशा मुक्त गाँव को प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार – मुख्यमंत्री श्री चौहान

बेटी फ्रेंडली हो हमारी पंचायतें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए ग्रामवासियों का माना आभार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समरस पंचायतों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित

मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित करने वाले ग्रामवासियों का आभार माना।

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त गाँव को विशेष रूप से 2 लाख रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायतें "बेटी फेंडली" हों। समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान, सम्मान और इज्जत बढ़े। बेटा-बेटी को बराबर माना जाए। माँ, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समरस पंचायतों को अपने काम से पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत करना है। जनता की सेवा, गाँव का विकास, आँगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत, सामुदायिक भवन का व्यवस्थित और परिणाममूलक संचालन हमारी प्राथमिकता हो। हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायत में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित करने वाले ग्रामवासियों का आभार माना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नारी सशक्तिकरण को समर्पित गीत की ध्वनि के साथ दीप प्रज्ज्वलन तथा कन्या-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास आये पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री सीताराम आदिवासी सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन किया गया। नर्मदापुरम जिले की तहसील बनखेड़ी की ग्राम पंचायत उमरधा की निर्विरोध निर्वाचित सरपंच सुश्री जागृति सिंह जूदेव और सीहोर जिले के बुधनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चिपरी के निर्विरोध निर्वाचित सरपंच श्री अमित चौहान ने अपने अनुभव तथा ग्राम विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएँ और कार्य-योजना प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर 5 लाख रूपए, सरपंच पद के लिए वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर 7 लाख रूपए तथा सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होने पर 7 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होने पर पंचायत को 12 लाख रूपए और पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में ही पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ कर्मठता की कोई कमी नहीं है। इंदौर ने महिला महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता के क्षेत्र में देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि जनता की सेवा और गाँव के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समरस पंचायतों को अपनी प्राथमिकता तय कर कार्य करना होगा। हम यह प्रण लें कि गाँव में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। यदि कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाएगा, जिससे हम अपना समय और पैसा कोर्ट-कचहरी में बर्बाद नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी हमारी प्राथमिकता हो कि केन्द्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाए। ग्राम पंचायत में सभी लोग मिल-बैठकर अगले पाँच साल की विकास की कार्य-योजना तय करें और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत में स्वच्छता, वृक्षारोपण, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, दिव्यांगों का सर्वे कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराना, गाँव को नशा मुक्त करना, गाँव में असामाजिक तत्वों और अवैधानिक गतिविधियों को न होने देना प्राथमिकता में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मियों को महाविद्यालयीन स्तर पर प्रवेश पर दो किस्तों में 25 हजार रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कॉलेज स्तर की पढ़ाई की नि:शुल्क व्यवस्था की जाएगी। मेधावी विद्यार्थियों को भी राज्य शासन निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय प्रतिमाह 10 हजार रूपए सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत रहने का भी आहवान किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव-गाँव में अमृत सरोवर तथा अन्य जल संरचनाएँ बनाकर पानी बचाने के काम को प्राथमिकता पर लिया जाए। साथ ही सौर ऊर्जा को अपनाने और बिजली बचाने की गतिविधियों को भी हमें आत्मसात करना होगा। हमें सिंचाई के लिए जल कर तथा अन्य करों को समय से चुकाने की आदत डालनी होगी, इससे प्राप्त राशि ही विकास का आधार है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गाँव अपना गौरव दिवस अवश्य मनाएँ। इस दिन गाँव के सभी लोग गाँव में एकत्र होकर विकास की योजना तय करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर माह ग्राम सभा हो। हमें विकास का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा-स्त्रोत बने।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने निर्विरोध निर्वाचन से पंचायतों का गठन कर देश में अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। पंचायत प्रतिनिधियों को विकास गतिविधियाँ संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से समर्पण और ईमानदारी से कार्य करते हुए समरसता के भाव का विस्तार करने की अपील की।

सहकारिता का 100वाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विश्व में सहकारी आंदोलन का प्रचार करना, आर्थिक क्षमता बढ़ाना, समानता व विश्व शांति के लिये काम करना है। इसे मनाने की शुरूआत सन् 1923 में की गई थी। सन् 1995 से ICA व COPAC मिलकर प्रतिवर्ष इसे मनाने का नारा (थीम) तैयार करते है।

इस वर्ष 100 वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दिनांक 2 जुलाई, शनिवार को विश्व भर की सहकारी संस्थाओं द्वारा मनाया जावेगा। इस वर्ष की थीम "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है", सहकारिता द्वारा विश्व को एक बेहतर जगह बनाने में दिये गये अद्वितीय योगदान को दर्शाती है। सहकारी संस्थाऐं आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देते है, पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ते है, अच्छी नौकरियां पैदा करते है, खाद्य सुरक्षा में योगदान करते है, स्थानीय समुदायो के भीतर वित्तीय पूंजी रखते है, नैतिक मूल्य श्रृंखला बनाते है और लोगो की भौतिक स्थितियों और सुरक्षा में सुधार करके सकारात्मक शांति में योगदान करते है। इस तरह एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान देते है।

सहकारिता दो शब्दो 'सह+कारिता' के मेल से बना है। जिसका आशय मिल जुलकर कार्य करना है। सहकारी संगठन के सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिये मिलजुल कर कार्य करते है। यह "एक सबके लिये और सब एक के लिये" की भावना पर आधारित एक जीवन पद्वति है। सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो लोकतंत्र, समानता तथा आत्म सहायता के आधार पर निजी हित तथा सम्पूर्ण समुदाय के हित के लिए काम करता है। यह एक सामाजिक तथा आर्थिक आंदोलन है, जिसका आधार सेवा है, न कि लाभ। सहकारिता कमजोर वर्गो के लोगो का आर्थिक उत्थान करती है, अमीर–गरीब के बीच की खाई को पाटती है व समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा करती है। इतनी आदर्श कार्य पद्वति विश्व में अन्य कोई हो ही नही सकती।

खुली एवं स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता तथा स्वाधीनता, शिक्षा प्रशिक्षण एवं संसूचना, सहकारिताओं में सहयोग, समुदाय के लिए सरोकार ये सहकारिता के सात सिद्वान्त है, जिसके अंर्तगत सहकारी संस्थाऐं कार्य करती है। सहकारिता का सतरंगा ध्वज आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, कृषि, उद्योग तथा कला व शिक्षा स्वाधीनता का उद्घोष करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में ये सात ही प्रमुख कारक होते है जिसकी पूर्ति सहकारिता के माध्यम से वह ससम्मान कर सकता है। स्पष्ट है कि सहकारिता से बढ़कर लोकतांत्रिक, जन हितेषी, परोपकारी ओर कोई पद्वति विश्व में नही है।

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। सहकारिता, ग्रामीणो को उचित मूल्य पर खाद, बीज, राशन व ऋण उपलब्ध करवाती है। सहकारिता के कारण ही कोरोनाकाल में खाद्यान्न की कमी नही हुई, नही तो स्थिति विकट हो जाती। ग्रामीण इलाको में कोरोना प्रोटोकॉल का प्रचार व टीकाकरण में सहकारिता के सहयोग को भुलाया नही जा सकता। आम आदमियों के लिये शहरो में अपने मकान की कल्पना को सहकारी गृह निर्माण समितियों के माध्यम से ही साकार करना सम्भव हो सका है। दूध व उससे बने पदार्थो की सुगम आपूर्ति में सहकारिता की श्वेत क्रांति का अहम योगदान है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहकारिता पीछे नही है। हर खुशी में मिठास घोलने वाली शक्कर के निर्माण में सहकारी शक्कर कारखानो का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी कपडा मिले व हेंडलूम सस्ते व उत्तम गुणवत्ता के कपडे बनाने के लिये विख्यात है। यह सूची बहुत लम्बी है। इस तरह सहकारिता ने मानव को रहने के लिये एक बेहतर विश्व का निर्माण किया है। सहकारिता ने कभी हथियारो का निर्माण नही किया जो विध्वंस का कार्य करते है। सहकारिता की सोच सकारात्मक है।

एक ऐसी मानव हितेषी कार्यप्रणाली से जुडे होने पर गर्व की अनुभूति होती है। आईये हम सहकारिता के शताब्दी दिवस को उत्साह से मनाये। इस दिन सतरंगा झंडा फहराकर सहकारिता का गीत गाये। गोष्ठियों का आयोजन करे जिसमें सहकारिता की सफलता का जश्न मनायें व समस्याओं के निराकरण पर चिंतन करें। युवा वर्ग को सहकारिता की ओर आकर्षित करने के लिये उन्हे सहकारिता की जानकारी दें व वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला का आयोजन करें। स्थानीय पत्र पत्रिकाओं व टीवी चेनलो में लेख, गतिविधियों की जानकारी आदि दे ताकि आमजन भी सहकारिता के बारे में जानकारी हासिल कर सके। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता शताब्दी दिवस की बधाई।

जय सहकारिता।

शिरीष पुरोहित
कम्प्यूटर प्रशिक्षक,
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022

सहकारिता के द्वारा बेहतर विश्व का निर्माण

सहकारिता का आस्था पर्व हर साल पूरे विश्व में जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है इसके कार्यक्रमों में आत्म–मंथन/चिंतन किया जाता है कि हम कहॉ थे कहां आ गये और किधर जाना है इस साल 100 वॉ अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई 2022 को मनाया गया, जिसकी मुख्य थीम "सहकारिता के द्वारा बेहतर विश्व का निमार्ण"। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का प्रमुख उद्देश्य जनता की चुनौतियों, समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों को जुटाने ओर मानवता की उपलब्धियों को बताते हुये सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करना है। विश्व के समस्त देशवर्ष में एक दिन एक मंच पर एकत्रित होकर जनता/जन मानस के कल्याण उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक/पर्यावरण संबंधी विषयों पर परिचर्चा कर उनके लक्ष्यों, आवश्यकताओं एवं स्वरोजगार उपलब्धि प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर उनके सम्पूर्ण विकास की कार्य योजना तैयार किया जाना ताकि उनके लक्ष्यों को पूरा कर विश्व/देश के बेहतरनिमार्ण की आधारशिला रख सके।

महामारी एवं मंदी के दौर में सहकारिता के लिये नई चुनौतियां तथा नई संभावनाये उभरकर सामने आई है। बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के कारण जो असंतुलन तथा असमानता का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के विभिन्न अंचलों में देखा जा रहा है, उसका समाधान सहकारिता के क्षेत्र से ही मिल सकता है। बेरोजगारी, मंदी, मंहगाई के शोषण के दुष्प्रभावों का निदान करने के लिये सहकारी क्षेत्र को ही आगे आना होगा, क्योकि यह वैचारिक धरातल तथा शक्ति सहकारिता की विचार धारा से ही मिल सकती है कि नई अर्थव्यवस्था का उत्तर व्यापक समाज हित में किस प्रकार किया जा सकता है।

"सहकारिता के द्वारा बेहतर दुनिया का निर्माण "पर विश्व के सभी सहकारी कार्यकर्ता / पदाधिकारी गण/कर्मचारी गण/जनमानस को शामिल कर सहकारी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। समुदाय के नैतिक मूल्यों/असमानता को कम करते हुये नई पीढी को नवीन सहकारी रोजगार की ओर अग्रसर कर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान तय किया जा सके। समाज का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त एव आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। सहकारी समितियों के विकास का केन्द्र बिन्दु उस संस्था का सदस्य ही है सदस्य के बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती।

वर्तमान परिदृश्य में सहकारी संस्थाओं सदस्य गणों की विचारों में असमानता, कार्यो में सहभागिता न होना, टीम वर्क में काम न करना, प्रशिक्षण के प्रति रूझान नही होना सहकारी आंदोलन की बहुत बडी बाधा है जिसे दूर किया जाना अति आवश्यक है। सदस्यों में सहकारी मूल्यों, जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, एकजुटता, ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों का विकास एवं सहकारी सिद्धांतो के प्रति जागरूक किया जाना अति आवश्यक है। जिससे सहकारिता के साथ–साथ समाज, कस्बा, जिला, राज्य, देश एवं दुनिया को एक नया वातावरण प्रदान कर उनके आर्थिक/सामाजिक/राजनैतिक सहभागिता कर सहकारिता की भावना"एक सबके लिए सब एक के लिये" की सार्थकता को पूरा कर पायेंगे।

सहकारिता अमृतकार समान समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कराना अतिआवश्यक है क्योंकि आज भी कुछ अनछुऐ क्षेत्र जिसमें हम कदम नही रख पाये वह क्षेत्रों को सहकारिता से जोडकर एक नया परिवेश सहकारिता के नवीन क्षेत्रों पर पदार्पण कर जनसमुदाय को लाभान्वित कर देश में सहकारिता को आगे ले जा पायें। देश में सहकारिता के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। साथ ही सहकारिता विश्वविघालयों का गठन कर आने वाली पीढी को सहकारिता की जानकारी/जागरूक/सशक्त एवं मजबूत कर नित नये क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कर सकते है।

आज आवश्यकता है सदस्यो को सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण/नवीन तकनीकी, सूचना केन्द्रो एवं मीडिया के माध्यम से जोडने का प्रयास किया जाना चाहिये जिससे सहकारिता के विकास में प्रत्येक वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर रहता है उस तक पहुंच पाये। ओर उसे सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों एवं उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति जागरूक करे।

देश में अमूल, इफको, कृभको, वारना शुगर मिल एवं इंडियन काफी हाउस जैसी संस्थाओ ने न केवल देश में बल्कि विश्व में सहकारिता की अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 के अवसर पर विश्व/देश के समस्त सहकारी कार्यकर्ता/पदाधिकारी गण/कृषक गण एवं आमजन मानस को हार्दिक शुभकामनाऐं एवं बधाईयॉ।

व्ही.के. बर्वे, प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र,जबलपुर

सहकारिता द्वारा बेहतर विश्व का निर्माण

सहकारिता के मुख्य सात सिद्धांत हैं

प्रस्तावना : जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जुलाई के प्रथम शनिवार को अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जायेगा। जो कि इस वर्ष 2 जुलाई को 100 वॉ सहकारिता अर्न्तराष्ट्रीय दिवस मनाऐंगे जिसकी थीम है (Cooperatives Build a Better World) 2 जुलाई 2022.

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना विश्व में आर्थिक क्षमता बढ़ाना, सहकारी आंदोलन का प्रचार–प्रसार करना, समानता व विश्व शांति के लिये काम करना है। सन् 1995 से ICA व COPAC मिलकर प्रतिवर्ष इसे मनाने का नारा (थीम) तैयार करते हैं। अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने की शुरूआत सन् 1923 में प्रथम बार की गई थी।

सहकारिता के पॉच अक्षर

स– सहयोग, सौहाद्र, सत्य, संकल्प, सदाचार

ह– हरसिद्धि, हितकारी, हिम्मत,

का– कामनारहित, कर्मप्रधान, कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्यकुशलता

रि– रीति, नीति, रिद्धि, सिद्धि

ता– तारण, तृप्ति, तपस्या

आज हम अपने देश एवं प्रदेश में समाजवादी, समाजव्यवस्था, लाने हेतु कृत संकल्प हैं, समाज से गरीबी, शोषण एवं असमानता दूर करने के लिए सहकारिता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः हमारे देश एवं प्रदेश के गरीब व निम्न तबके के लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने एवं उत्पादन बढ़ाने में सहकारिता एक अहम भूमिका निभा रहा है। देश की राष्ट्रीय योजनाओं में भी सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा गया है। देश की सभी प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निदान सहकारिता से संभव हो सकता है।

1. खुली एवं ऐच्छिक सदस्यता
2. लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण,
3. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी,
4. स्वायत्तता तथा स्वाधीनता,

5. शिक्षा प्रशिक्षण एवं संसूचना,
6. सहकारी संस्थाओं में सहयोग,
7. समुदाय के प्रति निष्ठा (समाज के हित की चिंता)

समुदाय के लिए सरोकार ये सहकारिता के सात सिद्धांत हैं इसके अन्तर्गत सहकारितायें कार्य करती हैं। सहकारिता का सतरंगा ध्वज (झण्डा) आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, कृषि, उद्योग तथा कला व शिक्षा स्वाधीनता का उद्घोष करता है किसी व्यक्ति के जीवन में ये सात ही प्रमुख कारक होते हैं जिसकी पूर्ति सहकारिता के माध्यम से व ससम्मान कर सकता है। स्पष्ट है कि सहकारिता से बढ़कर लोकतांत्रिक जन हितैषी, परोपकारी और कोई पद्धाति विश्व में नहीं है।

सहकारिता दो शब्दो के संधि से बना है सह+कारिता जिसका अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारी संगठन के सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित के लिए मिल–जुल कर कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक सबे लिये और सब एक के लिए की भावना पर आधारित एक जीवन पद्धति है। सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का एच्छिक संगठन है जो लोकतंत्र, समानता तथा आत्म सहायता के आधार पर निजी हित तथा सम्पूर्ण समुदाय के हित के लिए काम करता है। यह एक सामाजिक, आर्थिक, जनआंदोलन है जिसका आधार सेवा करना है न कि लाभ कमाना। सहकारिता कमजोर वर्गों के लोगों का आर्थिक उत्थान करती है, अमीर–गरीब के बीच की खाई को पाटती है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा करती है। सहकारिता जैसी आदर्श कार्य की पद्धाति विश्व में अन्य कहीं ओर हो ही नहीं सकती।

समिति के लाभ–हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते है, अपने उदेश्यों के अनुसार सहकारी समितियॉ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं।

1. कृषि सहकारी समिति
2. दुग्ध सहकारी समिति
3. उपभेक्ता सहकारी समिति
4. गृह निर्माण सहकारी समिति
5. सहकारी साख एवं बचत समिति
6. क्रय विक्रय सहकारी समिति

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है कृषि हमारे देश में आर्थिक विकास की आधार शिला है कृषि के विकास पर ही देश का आर्थिक विकास अवलंवित है। अतः हमारी सभी योजनाओं के केन्द्र में कृषि विकास को मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।

मंत्र केवल आज है, एक विश्व मानव के लिए।
सब मिले और एक हों, एक हो सबके लिए।।

विश्व एवं भारत में सहकारिता का इतिहास

सहकारिता आंदोलन सदस्यों द्वारा सदस्यों के लिए संचालित कार्यक्रम है। विश्व में सहकारिता आंदोलन की शुरूआत इंग्लैड के लंकाशायर में हुई, यहॉ पर रोबर्ट ओवन द्वारा सहकारी उपभोक्ता भंडार प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात हरसन शुल्ज डेलिश एवं फडरिक विलियम रैफेजन में जर्मनी में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात किया। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारम्भ दुर्भिक्ष आयोंग से माना जाता है, (जो 20वीं सदी से प्रारम्भ हुआ), जिसकी अनुशंसा पर सहकारी साख अधिनियम 1904 पारित किया गया। 1919 के अधिनियम में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में राज्य सूची में स्थान दिया गया। सहकारी समितियों की देख–रेख तथा सहकारिता विकास के लिए भारत में राज्य संघ सहकारिता विभाग कार्यरत है। यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सहकारी समिति के सदस्यों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों का मार्ग दर्शन करता है।

मुझे एक ऐसी मानव संसाधन, मानव हितैषी कार्य प्राणाली से जुडे होने पर गर्व का अनुभव होता है आईये हम सब सहकारिता के शताब्दी दिवस को उत्साह पूर्वक एवं हर्ष व उल्लास के साथ मनाये इस दिन अपनी संस्थाओं में सतरंगा झण्डा फहरायें एवं सहकारिता के गीत गायें एवं सहकारिता अमर रहे के नारे लगायें और सहकारी संघोष्टियों का आयोंजन करें जिसमें सहकारिता के सफलता की कहानी का जश्न मनाये व अपने संस्था एवं संस्था से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का चिंतन कर समस्याओं का हल ढूढ़े एवं सहकारिता का प्रचार–प्रसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनलों में सहकारिता की गतिविधियों की जानकारी दें, ताकि सहकारी समितियों से जुड़े कार्यकर्ता, समिति के सदस्ययों एवं आम किसानों नागरिकों को सहकारिता के बारे में जानकारी दें, जिससे आम जन भी सहकारिता की जानकारी हांसिल कर सहकारिता से लाभ उठा सकें।

सहकारी ध्वज के सात रंग का प्रतीक

1. लालरंग– आर्थिक स्वाधीनता (चीन, जापान, कोरिया, रूस, कोलम्बिया, कम्युनिष्ट कलर)
2. केशरिया– सामाजिक स्वाधीनता (हमारी अर्थ संस्कृत का स्वरूप समाजवाद)
3. पीलारंग– नैतिक स्वाधीनता (शुभ रंग माना जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक)
4. हरारंग– उत्पादन स्वाधीनता या हरित क्रान्ति (हरियाली हरित क्रान्ति)
5. आसमानी रंग– राजनैतिक स्वाधीनता (राजनीति हो लेकिन छल–कपट न हो देश के विकास के लिए राजनीति)
6. गहरा आसमानी रंग– उद्योग एवं व्यापार स्वाधीनता।
7. बैगनी या कत्थई रंग– सहकारी शिक्षा एवं कला स्वाधीनता (सहकारी शिक्षा–प्रशिक्षण की सभी को जानकारी हो)

शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारिता का एक बुनियादी सिद्धांत है सहकारिता एक प्रजातांत्रिक जन आंदोलन होने के नाते यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, सदस्यों, एवं भावी सदस्यों को तथा आम नागरिकों को सहकारिता की शिक्षा दी जावे । तथा वैतनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे जिससे वे अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर सकें।

शिवकुमार गौतम, प्राचार्य,सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगॉव,छतरपुर

सहकारिता से ही सर्वांगीण विकास संभव हैं - श्री रंजन

100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर संघ में ध्वजारोहण

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। आचार संहिता का पालन करते हुए इस वर्ष 100 वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष की विषय वस्तु ''सहकारिता के द्वारा विश्व का निर्माण'' है। दिनांक 02 जुलाई 2022 (माह के प्रथम शनिवार) के अवसर पर संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा सहकारी सतरंगा झण्डा फहराय गया । श्री रंजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारिता में सब एक के लिए एक सबके लिए की भावना से सभी को कार्य करने चाहिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नवीन सहकारिता मंत्रालय का गठन, भारत सरकार द्वारा समस्त भारत में 63000 हजार पैक्स संस्थाओं को कम्प्यूटरीकरण, सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो सहकारी बंधुओं के लिए उल्लेखनीय कार्य है। सहकारिता ही एक ऐसा मॉडल है जो देश ही नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए उपयोगी है। जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक एवं मानव जाति का सर्वांगीण विकास सम्भव है। सहकारिता मिलजुल कर रहना सिखाती है। अमूल, इफको, कृभकों, सांची दुग्ध संघ इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस अवसर पर संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य श्री ए.के. जोशी, प्राचार्य श्री जी. पी. मांझी, लेखाधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल, राज्य समन्वयक श्री संतोष येड़े, कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान एवं सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची एएफसी इंडिया की टीम

नौगांव प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य से ली संस्था की जानकारी

छतरपुर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव का दिल्ली से आए हुए प्रोजेक्ट ऑफीसर आर. बी.पी. सिन्हा व रिसर्च एसोसिएट के अधिकारी कुश मेंहदीरता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धाराशाई व जर्जर हुई केन्द्र की बिल्डिंगों की जानकारी प्राचार्य शिवकुमार गौतम से ली। कंप्यूटर लैब, छात्रावास, सरकारी कर्मचारियों के आवास एवं एचडीसीएम कोर्स एवं शिक्षा प्रशिक्षण की गतिविधिया की क्लास आदि का मुआयना किया गया जो कि सभी पूर्णतया धराशाई हो चुकी है। साथ ही टीम ने मप्र राज्य संघ के प्रबंध संचालक ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक संजय सिंह एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव प्राचार्य शिवकुमार गौतम के कार्य की सराहना की और कहा कि ऐसे ही जज्बात वाले अधिकारियों की आवश्यकता मप्र राज्य संघ में है।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य शिवकुमार गौतम ने दिल्ली की आई हुई टीम का आभार व्यक्त किया। टीम ने जल्दी ही मेटीनेंस कराने एवं कुछ परिसर में नए सामान कुर्सी, टेबल, अलमारी आदि देने की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने की बात कहीं है।

इस मौके पर दिल्ली से आई हुई एएफसी की टीम के प्रोजेक्ट ऑफिसर आर. बी.पी. सिन्हा, रिसर्च एसोसिएट कुश मेंहदीरता, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य शिव कुमार गौतम, प्रशिक्षक हृदेश कुमार, भृत्य एवं प्रभारी लिपिक खूबचंद नाई, स्वीपर राजकुमार डुमार, नाइट गार्ड भूपेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित,
भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

शीघ्र आयें प्रवेश पायें

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-

संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल
फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।